माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या भारत सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): माननीय सभापति महोदय, दलहन की कई किस्मों में से कुछ की पैदावार अधिक होती है, कुछ की कम होती है, जिसमें से तूर दाल के बारे में कहा गया है। यह सबकी जानकारी में है कि पिछली बार कर्णाटक में सूखे के कारण अच्छी फसल नहीं हो पाई और जो तूर दाल होती है, उसके उत्पादन में बहुत अधिक समय लगता है। चना दाल का उत्पादन अधिक है। देश में कुल दालों का जो उत्पादन हुआ है, उसके अनुसार वह सरप्लस है, लेकिन तूर दल की जितनी आवश्यकता है, उसमें कमी आई है।

सर, माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एमएसपी के बारे में माननीय मोदी जी की गारंटी है। किसानों की आय दोगुनी हो, उनकी लागत का लाभ अच्छे ढंग से मिले, यह अपने आपमें मोदी जी की गारंटी है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: Hon. Member Kavita Patidar to move that an Address be Presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2024."

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए:-

"कि राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2024 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

सभापति महोदय, 'अमृत काल' की शुरुआत में बने नये संसद भवन में अपने जीवन को कर्म से गढ़ने वाली नारी-शक्ति की परिचायिका, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 500 साल के इंतजार

के बाद बने भव्य अयोध्या मंदिर एवं रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के मनोभावों के साथ ही रामराज्य की स्थापना की ओर कदम उठाते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नये भवन की भव्यता को तो उन्होंने दर्शाया ही है, साथ में विश्वास भी जताया है कि विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति के रचनात्मक संवाद इस नई बिल्डिंग के गवाह बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जैसा हम जानते हैं कि हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण में उठाए गए कदम हर स्तर पर किए गए संभव प्रयास हैं। उद्यमिता, सुगम जीवन, महिलाओं के लिए सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को इन 10 वर्षों में जो गति मिली है, वह हम सबके सामने है। *"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः",* इस मूलमंत्र पर केन्द्रित होकर माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा भी निर्धारित किया और उसको वास्तविकता का स्वरूप भी प्रदान किया। इसके साथ-साथ, उसने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की तकदीर सँवारने का भी काम किया, चाहे वह 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना' से तीन करोड़ से अधिक बहनों के पोषण की चिन्ता का विषय हो या फिर बहनों के सम्मान से जुड़ा 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर बुनियादी जरूरत को पूरा करने का प्रण हो। आज हमारी सरकार ने हर उस माता की चिन्ता समझी, जिनकी आँखों की रोशनी घर की रसोई में चूल्हा जलाते हुए धूमिल हो गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उस धुएँ से आज़ादी मिली, जिसने उनकी साँसों को दमा जैसी बीमारियों से जकड़ रखा था। माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों से करोड़ों बहनों ने बैंक की दहलीज तब लांघी, जब उनके जन-धन खाते खोले गए। आज हमारी सरकार के द्वारा 27 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन खाते खोले गए हैं। आज हमारी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक दिखाती गणतंत्र दिवस की परेड भी नारी शक्ति को समर्पित की गई थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारिता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उसी का परिणाम है कि आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, जिन्हें 8 लाख करोड़ रुपये बैंक लोन और 40 हज़ार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, one minute. Yes, Digvijaya Singhji, under which rule, are you raising a point of order?

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, Rule 258. The point of order is this. The procedure here is this.

MR. CHAIRMAN: Would you kindly look at Rule 258? ...(*Interruptions*)... Is it Rule 238? Please make up your mind. Is it Rule 238 or Rule 258? You will have to decide under which rule you are raising it.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the point is of procedure. When is the amendment to be moved?

MR. CHAIRMAN: Under which rule so that I may also have the benefit of it?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is Rule 258 -- Points of order and decisions thereon.

MR. CHAIRMAN: I gave no decision. I will read it. Rule 258 refers to points of order and decisions thereon. It says that any member may at any time submit a point of order for the decision of the Chairman, but in doing so, shall confine himself to stating the point.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Yes. Sir, the point is simple. The amendments are moved after the mover has moved the motion and seconded by the seconder and then come the amendments. After that, her speech will start. That is the procedure. ...(*Interruptions*)... That has been the procedure.

MR. CHAIRMAN: Can you indicate this procedure in the rule?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it is the procedure. This has been done over the precedents. This is the first time that she has started the speech without the amendments being moved.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, many things are happening for the first time.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: * ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, Digvijaya Singhji.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: Sir, I am very mindful of history and that is why I seek everybody's assistance.

---

* Not recorded.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have sought the advice of the officers here and they confirmed that usually the amendments are moved before her speech starts. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: There is no such provision of seconding. ...(*Interruptions*)... Take your seat. ...(*Interruptions*)... You are a very experienced Member. ...(*Interruptions*)... As a matter of fact, I am going by the Listed Business. ...(*Interruptions*)... Hon. Member may continue her address.

सुश्री कविता पाटीदार: माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। 'नमो ड्रोन दीदी योजना' के तहत समूह को 15 हज़ार ड्रोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह करना महिला सम्मान का एक सटीक उदाहरण है। सशस्त्र बलों में महिलाओं को पहली बार परमानेंट कमीशन देने का निर्णय हो या सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को पहली बार प्रवेश देने की बात हो - हमारी सरकार द्वारा दिए गए अवसर आज हमारी बहनों के विकास और सम्मान के रास्ते खोल रहे हैं। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं और नौसेना के जहाज़ को भी कमांड कर रही हैं। वे चंद्रयान-3 की सफलता में भी भूमिका निभा रही हैं और कोविड जैसे संकट के समय अपने धैर्य और मनोबल को ऊंचा करते हुए वैक्सीन निर्माण में भी सहभागी बनी हैं। हमारी सरकार की मुद्रा योजना के तहत करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं, जिससे स्वरोजगार शुरू कर बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। पहली बार भारत के लिंग अनुपात में 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं तक सुधार आज हम देख रहे हैं।

महोदय, ट्रिपल तलाक को गैर-कानूनी बनाकर एक तरफ बहनों के सम्मान की रक्षा करने से लेकर इतिहास को बदलते हुए राजनीति के साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के सफर तक, 'पीएम आवास योजना' के तहत महिलाओं को मालिकाना हक देते हुए 70 प्रतिशत से अधिक घर देने के साथ ही नाबालिगों से बलात्कार के लिए मृत्यु दंड और न्यूनतम सजा को बढ़ाकर बीस साल तक किया गया। ये माननीय प्रधान मंत्री जी के वो संकल्प थे, जिनके द्वारा नारी के अधिकारों में वृद्धि कर उनके सम्मान की रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस प्रदेश से मैं आती हूं मध्य प्रदेश, जहां मां नर्मदा और मां शारदा का आशीर्वाद पग-पग पर मिलता है, उस प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, विवाह और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की सभी योजनाओं के साथ केन्द्र की योजना का लाभ लेकर महिला क्रांति का सामाजिक प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है।

'घर-घर आंगन देखो खुशहाली आई है,
सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है।'

यह सुअवसर मिला है, क्योंकि आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। हमारी सरकार ने बहन-बेटियों के जीवन-चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसका समाधान किया है। महिला शक्ति के साथ ही युवा शक्ति, किसान और गरीब-इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है। राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से अनेकों योजनाओं और नीतियों के माध्यम से हमारी सरकार विकास रथ पर आगे बढ़ रही है। सफल चन्द्रयान मिशन से लेकर हाल ही में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने देश के सम्मान को बढ़ाया है।

महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा है कि बीते दस वर्ष की साधना का यह विस्तार है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जो संशाएं थीं, आज वे इतिहास बन चुकी हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में भी बहुत कमी आई है। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने 'One Rank One Pension' को भी लागू किया है, जिसका इंतजार काफी समय से था। देश सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे तेज गति से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज 'Top Five Economies' में हमारा भारत पहुंच चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। इसके साथ ही सफलता के साथ 'आदित्य मिशन' को भी लॉन्च किया। दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस के साथ भारत के सबसे लंबे समुद्री 'अटल सेतु' के रूप में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत को अपनी पहली 'अमृत भारत ट्रेन' मिली। मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। भारत का निर्यात 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI दुगना हुआ है। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादनों की बिक्री में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। Start ups बढ़कर 1 lakh से अधिक हो गए हैं। GST देने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़, 40 लाख हो गई है। 2023-24 में 12 lakh electric वाहन बिके हैं, जो एक नई क्रांति का आह्वान है। 'Make in India' और 'आत्मनिर्भर भारत' हमारी ताकत बन चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात देश बन चुका है। हम बचपन से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे थे, लेकिन आज हमारी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारा देश आगे निकला है। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन-देन का 46 प्रतिशत भारत में होता है। आज गांव में चार लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो या नेशनल हाईवे की बात हो, एयरपोर्ट की संख्या दोगुना बढ़ाने के साथ ही 10 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना हो, हमारा देश तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

पांच शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाये गये हैं। आज 49 से ज्यादा रूट पर वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं। यह विकसित भारत के संकल्प की यात्रा का विकास रूपी प्रतिबिंब है।

सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की सराहना करती हूं। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने ओबीसी समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने के

लिए कई पहल की हैं। उनके नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियां मिलती हैं। यह मुझे उपलब्धि की भावना से भर देता है जब मैं यह उल्लेख करती हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी स्वयं ओबीसी श्रेणी से हैं, उनके मंत्रिमंडल में कई मंत्री ओबीसी हैं, साथ ही मेरे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी ओबीसी श्रेणी से आते हैं। ऐसे कई निर्णय यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारी सरकार ओबीसी हितैषी है और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा**) *पीठासीन हुईं*]

सुश्री कविता पाटीदार: उपसभाध्यक्ष महोदया, भव्य अयोध्या मंदिर और श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे गौरव का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक पल एक प्रकाश पुंज है, जो हमें एकता, नैतिक मूल्यों और हमारे महान राष्ट्र की भावना से मेल खाने वाले सिद्धांतों की ओर मार्ग दर्शित करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए, आइये, हम सबका साथ, सबका विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, यह मानते हुए कि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है,

'सूरज जैसा बनना है, तो सूरज जितना जलना होगा,
नदियों सा आदर पाना है, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा,
हम इस सदी के लोग हैं, तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी,
अगर मोदी की गारंटी है, तो हर मुश्किल अब हल होगी।'

इस भाव के साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना, उसके भाव हम सब के दिलों में गूंजें और उसकी सफलता के सामूहिक प्रयास के आह्वान हेतु पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत !

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा**) **:** धन्यवाद। श्री विवेक ठाकुर जी।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार)**:** आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नये संसद भवन में प्रस्तुत राष्ट्रपति के प्रथम अभिभाषण पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मुझे अवसर प्रदान किया। महोदया, आज भले ही हम नये संसद भवन में प्रवेश कर चुके हों, परंतु पुराने सदन की एक स्मृति संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा -

'सर्वदा स्यान्नपः प्राज्ञ,
स्वमते न कदाचन।
सम्याधिकार प्रकृति,
सभासत्सुमते स्थितः ।।'

यह श्लोक लिफ्ट नम्बर चार के पास स्थित गुम्बद पर अंकित है। पद्म पुराण में इसे सर्वलोक सुख प्रदम् कहा गया है, सांख्य दर्शन में इसे अत्यंत लोकहितम् सत्यम् कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि राजा को हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए। बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना से निर्णय लेने की क्षमता प्रामाणिक होती है। उन्हें यह सुनना चाहिए कि सदन में अन्य लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसे सभी की भलाई के लिए कार्य करना है। उपसभाध्यक्ष महोदया, आप सोच रही होंगी कि मैंने उपरोक्त श्लोक की चर्चा क्यों की? वह इसलिए की क्योंकि उपरोक्त श्लोक में प्रधान सेवक से जो अपेक्षा की गई है, उन सभी की पूर्ति हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने पिछले दस वर्षों में की है। यह बजट देखकर यही प्रतीत होता है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना से जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वह साफ-साफ परिलक्षित होता है, वरना हमने कितने चुनावी वर्ष के बजट देखे, जिनमें freebies की भरमार होती थी, परंतु यह बजट भारत के अमृतकाल का बजट है, जिसमें 2047 में विकसित भारत के roadmap को जुलाई में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह एक दूरदर्शी सोच के बजट की झलक है, क्योंकि यह interim budget है। जब दूरदर्शिता की बात आती है, तो पूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा इस सदन में demonetisation पर दिया गया बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने केन्स, जो एक बहुत ही नामी-गिरामी इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें क्वोट किया था और कहा था कि वर्तमान सरकार जो नीति लेकर आई है, उससे वह दूरदर्शी लाभ की अपेक्षा कर रही है, पर केन्स का कहना है, "In the long-run, we are all dead." अर्थात् हमें निकट भविष्य की चिंता पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य की दूरदर्शी योजनाओं पर। विचार कीजिए कि ऐसे विचार वाली सरकार ने देश पर दशकों तक राज किया और इसी दूरदर्शिता का अभाव था कि जब 2014 में हम सत्ता में आए, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह स्थिति में थी। अगर मैं उन्हीं पूर्व प्रधान मंत्री जी के उस समय के एक और बयान का जिक्र करूं, जब उन्होंने demonetisation को organised loot and legalised plunder कहा था, तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि organised loot and legalised plunder उसे कहते हैं जब देश में oil bonds के माध्यम से तेल खरीदा जा रहा था ताकि भुगतान मौजूदा वित्तीय वर्ष में न करना पड़े और current account deficit कम दिखे। महोदय, organised loot and legalised plunder तब होता है, जब बजट में loss or borrowings को carry forward करके fiscal deficit को paper पर limit में रखने का प्रयास किया जाता था, लेकिन वह वास्तव में अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा होता था। महोदय, organised loot and legalised plunder तब होता है, जब 2G घोटाला होता है, कोल घोटाला होता है, कॉमनवैल्थ गेम्स घोटाला होता है, अगस्टावैस्टलैंड घोटाला होता है। यह सब एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री और अर्थशास्त्री वित्त मंत्री की नाक के नीचे होता था और वे दोनों अभी भी इस सदन के सदस्य हैं। जनता से खुलेआम ऐसी * की गई थी कि आदमी जिसका कम वर्णन करे, वही उचित है। वह सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि दूरदर्शिता का अभाव था और राष्ट्र के प्रति समर्पण नगण्य था, भाव एक जमींदार और जागीर का था और एक चरमराई अर्थव्यवस्था के साथ हमारा सरकार में गृह प्रवेश हुआ था।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

सभापति महोदय, जब हम 2014 में आए और इकोनॉमी की समीक्षा की तो हालात भयावह थे। एक जोरदार बहस छिड़ी कि state of economy पर White Paper लाया जाए और देश और दुनिया जाने कि किस अवस्था में देश आकर खड़ा है। ऐसा बोला ही जाता था कि भारत fragile five में है, policy paralysis से ग्रसित है, banks bad shape में हैं और borrowings fiscal mismanagement का अहम हिस्सा बन गया था। मैंने पहले भी जिक्र किया है।

महोदय, inflation out of control था, लेकिन उस White Paper को तब लाने पर हालात ऐसे बन जाते कि सारे investors भाग जाते और India investment story तहस-नहस होनी तय थी। वहाँ से प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दस साल के आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्ध भारत की जिस यात्रा पर हम चले, उससे आज fragile five से विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बने ही, साथ ही fastest growing economy का सेहरा पहनकर हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहे हैं। महोदय, बाधाएं तो ऐसी आईं कि विश्व हिल गया, कोविड जैसी महामारी ने world economy को हिला दिया और geopolitical हालात, युद्ध आदि सभी कुछ एक साथ होकर एक नए world order को भी स्वरूप देने लगे, लेकिन हमारा भारत अग्रणी होकर इन सबके बीच से एक bright spot बनकर निकला। आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसी सत्र में सदन में वह White Paper जरूर लाएं, ताकि देश यह जाने कि इन्होंने हमें कहाँ लाकर खड़ा किया था और आज हम देश को दस वर्षों में कैसे-कैसे निकालते हुए भारत को bright spot बना बैठे हैं। एक चमकता हुआ सितारा, जिसको विश्व अब हर समस्या के निदान के लिए आशाभरी निगाह से देखता है। आप जान लें कि बिना भारत के पोज़िशन तय किए, global opinion अब shape up नहीं करती है। इसके साथ-साथ मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की foreign policy का transformation जिसमें इंडिया फर्स्ट आया, वह एक केस स्टडी बन चुका है। आज के इस भारत पर हमको नाज़ है और गर्व भी है। 2014 के पूर्व महंगाई की क्या स्थिति थी, inflation rate out of control था। उस समय की स्थिति को देखकर एक German economist, Dr. Karl Pohl का इन्फ्लेशन के संबंध में एक क्वोट याद आता है। "Inflation is like toothpaste. Once it's out, you can hardly get it back in again." इसी प्रकार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Harry Truman ने कहा था कि a recession is when your neighbor is out of work, a depression is when you are out of work. आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने economic recession और economic depression दोनों से हम भारतीयों को बचाया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, देश को बांटने का हाल फिलहाल एक जबर्दस्ती का विवाद खड़ा किया गया और पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन भारत की जनता ने इतना बुरे तरीके से बीते चुनाव में इनके इरादों पर पानी फेर दिया कि ये समझ ही नहीं पाए। हमारी सरकार ने चार जातियों को विकास के लिए बेंचमार्क बनाया है और यह सम्पूर्ण सच है - गरीब, किसान, महिला और युवा। प्रधान मंत्री जी का तो यह स्पष्ट मानना है कि यदि हम इन चार जातियों का उत्थान करते हैं, तो देश का उत्थान स्वतः हो जाएगा और यह सही भी है। इसलिए पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 4 करोड़, 10 लाख लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए गए। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे। करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधान मंत्री

गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन प्रदान किया जा रहा है। 51.5 करोड़ पीएम जनधन अकाउंट खोले गए और यह financial inclusion का विश्व में एक अदभुत उदाहरण बना। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन वितरित किए गए। पहली बार आज़ाद भारत में किसी सरकार ने समाज के इस वर्ग की भी चिंता की है। यह एक अदभुत मिसाल कायम हुई है। हमारी इन्हीं जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा था कि पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को multi-dimensional poverty index से बाहर निकाला है। इसलिए कहा जाता है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अगली जाति - किसानों पर आता हूं। देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और शोधक, स्वर्गीय एम. एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि if agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. यह सच भी है। आज हमारी अर्थव्यवस्था के अन्नदाता के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कोविड के समय हमारे अन्नदाता ही थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के इंजन को गति प्रदान की। इसलिए प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाताओं को सहायता प्रदान करने हेतु, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई और आज लगभग 11.8 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि वितरित की जा चुकी है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जा चुका है। अब तो ड्रोन दीदी के माध्यम से आज महिला समूह को ड्रोन के माध्यम से किसानी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यूरिया के बढ़ते उपयोग को सीमित करने हेतु नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका जिक्र इस इंटेरिम बजट में भी किया गया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां जल में arsenic की समस्या बहुत अधिक है। केवल बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यह समस्या अति गंभीर है। इस योजना से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने जा रहा है। Soil or ground water management improvement की दिशा में यह बहुत बड़ी पहल है। आज 1361 मंडियों को eNAM के तहत डिजिटल रूप में जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। अब मैं अगली जाति - महिला पर आना चाहता हूं। कौटिल्य ने कहा था -

"न स्त्रीरत्नसमं रत्नम्"।

अर्थात् स्त्री के समान कोई रत्न नहीं है। महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, यह आदरणीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य रहा है और उसी दिशा में यह सरकार निरंतर काम कर रही है। इसलिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 25.86 लाख करोड़ रुपये 44.16 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए गए, जिसमें से 30 करोड़ लाभार्थी सिर्फ महिलाएं थीं । आज एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। इस बजट के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। हायर एजुकेशन में पिछले 10 वर्षों में फीमेल एनरॉलमेंट में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आज 37 प्रतिशत तक जा पहुँचा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट में आशा और आँगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत के तहत कवर करने की जो घोषणा की है, इससे इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। कोविड काल में गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे घुस कर जिस तरह से इन्होंने टीकाकरण कराया और देश को बचाया, यह एक उचित सम्मान देने वाला

कदम है। इसी संसद भवन ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं को समान भागीदारी दिलाने का ऐतिहासिक कदम भी उठाया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अब अगली जाति, यानी युवा शक्ति की बात करना चाहूँगा। कहते हैं न कि Europe has aged, China is aging and India is young. हमारी सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को पिछले 10 वर्षों में स्किल ट्रेनिंग प्रदान की है। 2014 में जहाँ 16 आईआईटीज़ थे, वहीं आज 23 आईआईटीज़ हैं; 2014 में जहाँ 7 एम्स थे, वहीं आज 22 एम्स हो चुके हैं; 2014 में जहाँ 723 यूनिवर्सिटीज़ थीं, वहीं आज 1,113 नई यूनिवर्सिटीज़ हैं। पीएम-श्री स्कूल्स के माध्यम से स्कूल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और इस बजट में धनराशि को 4,000 करोड़ से बढ़ा कर 6,050 करोड़ कर दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1 प्रतिशत से घट कर 3.2 प्रतिशत हो चुका है। खेलों में विश्व स्तर पर भारत के युवा खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है और 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। स्टार्ट-अप्स की संख्या बढ़ कर एक लाख हो चुकी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट की सफलता का मापन इससे होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 वर्षों में यह 5 गुना बढ़ कर इस साल 11.11 लाख करोड़ हो गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। यह तब संभव हो पाता है, जब आप फ्रीबीज़ की राजनीति को छोड़ कर देश के दीर्घकालिक विकास के बारे में सोचते हैं। जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के तहत राज्य सरकारों को भी कैपेक्स में बढ़ोतरी करने हेतु 50 वर्षों का ब्याज मुक्त लोन दिया गया और हम पर आरोप लगता है कि हम राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं! इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने उधर के गठबंधन के मित्रों के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा।

"तू इधर उधर की न बात कर ये बता कि क़ाफ़िला क्यूँ लुटा
मुझे रहज़नों से गिला नहीं तिरी रहबरी का सवाल है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, कैपेक्स में बढ़ोतरी का ही परिणाम था कि आज देश में गाँवों में लगभग 3.75 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो चुका है; राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90 हजार किलोमीटर से बढ़ कर 1 लाख, 46 हजार किलोमीटर हो गई है; चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई ढाई गुणा हो गई है; हाई स्पीड कॉरिडोर का 500 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर तक विस्तार हो चुका है; हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी 149 हो चुकी है। मतलब अनगिनत ऐसे काम हुए हैं, जो भूतो न भविष्यति की ही कैटेगरी में आते हैं। हाल में जो अटल सेतु के विकास ने भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया, यह भी एक अद्भुत मिसाल है, जो पूरी दुनिया देख रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से, पीएम गति शक्ति के माध्यम से तीन बड़े रेल कॉरिडोर्स की संकल्पना की गई है, जो एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर; दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है। जैसे मान लिया जाए कि दिल्ली और पटना का रूट है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, तो इससे यात्री सेफ्टी भी बढ़ेगी, टाइम में भी कमी आएगी और यह एक बहुत ही जरूरी पहल है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हर प्रकार के रॉ मैटीरियल्स उपलब्ध हैं, लेकिन एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई मैनेजमेंट का बड़ा इश्यू रहता है। जहाँ डिमांड है, वहाँ तुरंत सप्लाई हो, ऐसी योजनाएँ हमारे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाएँगी। जिस प्रकार दक्षिण में सीमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि आवश्यकता पूर्व में है, लेकिन यह कैसे तुरंत पहुँचे, यह सब कुछ यह योजना साकार करेगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होगा, जब इन सबका स्वरूप खड़ा होगा। महोदया, आम रेल यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत के समान 40,000 बोगीज़ बनेंगी और आम यात्रियों को भी बेहतर यात्रा कराने का एक बेंचमार्क तय हो चुका है।

महोदया, आधारभूत अवसंरचना की बात हो रही है, तो साथ ही साथ मैं इस सदन का ध्यान पिछले 10 वर्षों की अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हमने चंद्रयान-2 की विफलता देखी, लेकिन जैसा कि साहिर लुधियानवी कहते हैं कि :

"हज़ार बर्क गिरे लाख आँधियाँ उट्ठें,
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।"

और हुआ भी ऐसा। आज हम चंद्रयान-3 के माध्यम से और आदित्य-एल1 के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा तक पहुँच गये हैं।

हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वे जीएसटी का विरोध करते हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि *"हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या।"* अर्थात् सारे प्रमाण आपके समक्ष हैं। हमारी सरकार द्वारा टैक्स संरचना में जो आमूलचूल परिवर्तन किये गये, उनका नतीजा है कि जीएसटी आने के बाद 2018 में monthly GST collection 90,000 करोड़ से बढ़ कर अब average 1.7 लाख करोड़ प्रति माह हो चुका है। टैक्स संरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा आदरणीया वित्त मंत्री जी ने की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2010 के 25,000 तक के और वित्तीय वर्ष 2011 से 2015 के 10,000 तक के tax dispute को सरकार पूरी तरह withdraw करेगी, जिससे लगभग 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को लाभ होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा।

महोदया, आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यदि हम देखें, तो भारत का निर्यात 450 बिलियन डॉलर से बढ़ कर 775 बिलियन डॉलर हो चुका है, forex reserve आज 600 अरब डॉलर हो चुका है, mobile manufacturing में हम 5 गुना बढ़ोतरी कर चुके हैं और आज DBT के माध्यम से हम लगभग 2.25 लाख करोड़ की बचत कर चुके हैं। इन सबका श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के समक्ष खड़ा रहा और वे हैं - आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी। इसलिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी पर सिखों के महान गुरु, गुरु गोबिन्द सिंह जी, जिनका केन्द्र हमारा पटना साहिब रहा, उनकी एक पंक्ति है, जो बड़ी सटीक बैठती है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा :

"देह शिवा बर मोहे ईहे,
शुभ कर्मन ते कभुं न टरूं
न डरौं अरि सौं जब जाय लड़ौं,
निश्चय कर अपनी जीत करौं।
जब आव की अउध निदान बनै,
अति ही रन मैं तब जूझ मरों।"

जिसका अर्थ है - हे शिवा (शिव की शक्ति), मुझे यह वर दे कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी भी पीछे न हटूँ। जब मैं युद्ध करने जाऊँ, तो शत्रु से न डरूँ और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूँ। हम फिर जुलाई में आ रहे हैं।

महोदया, धर्म और अर्थ का बड़ा मजबूत सम्बन्ध होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारतवर्ष में बहुत सम्भावनाएँ अभी छिपी हुई हैं। अभी हाल में रामलला के भव्य मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा प्रधान मंत्री जी द्वारा की गयी। उसने अयोध्या की सूरत ही बदल दी। आज अयोध्या में एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, होटल्स बन रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, चार धाम कॉरिडोर और केदारनाथ का विकास किया, उससे लोकल अर्थव्यवस्था का बहुत अधिक विकास हुआ है। मैं हाल ही में तमिलनाडु गया था। वहाँ ऐसी पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। हमारे मन्दिरों में बहुत पोटेंशियल है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि आज भी कई ऐसे मन्दिर हैं, जिनके विकास से अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है।

स्पिरिचुअल टूरिज्म के प्रमोशन हेतु इस इंटेरिम बजट में चर्चा की गई है, जिसकी प्रतिभा as a sector - अभी देश में harness नहीं हुआ है और इसको बढ़ावा देना बहुत ही सकारात्मक कदम है, जो आने वाले समय में रोजगार के दृष्टिकोण से अपार opportunities को एक बहुत ही बड़ा स्वरूप दे सकता है। प्रभु श्रीराम की बात तो पूरा देश कर ही रहा है, प्रधान मंत्री जी ने प्राण-प्रतिष्ठा के बाद नयी सोलर पॉलिसी के तहत सौर ऊर्जा से जुड़ी अत्यधिक दूरदर्शी Rooftop Solarization योजना का शुभारम्भ किया, जिसमें 1 करोड़ उपभोक्ता 300 युनिट बिजली मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और सरकार को उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो एक सूर्यवंशी की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद उस दिन की एक अद्भुत घोषणा रही।

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और माननीया वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस इंटेरिम बजट में एक अद्भुत घोषणा की है। एक पॉलिसी डिसीज़न इस बजट के तहत किया गया है कि भारत सरकार आने वाले समय में "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु बना कर इंडिया की growth story तय करने जा रही है। पूर्वोत्तर का एक वासी होने के नाते इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदया, इस बजट की कई क्रांतिकारी घोषणाएँ हैं - मत्स्य पालन की दुनिया में 'Blue Economy-2' का आरंभ होना, देश में हर जिला स्तर पर हॉस्पिटल सेटअप करना, 9 से 14 वर्ष की बच्चियों का सर्वाइकल कैंसर रोधी टीकाकरण की शुरुआत करना - यह निर्णय हमारी सरकार की संवेदनशीलता का अद्भुत परिचायक है।

सब बात हो और डिजिटल क्रांति की बात न हो, जो विश्व में एक मिसाल बन चुका है। आज दुनिया के कुल रीयल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में ही होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1,200 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति, जिसको हम 'जैम ट्रिनिटी' भी कहते हैं, इनसे भ्रष्टाचार पर अद्भुत लगाम लगी है। यह सरकार अब तक डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर चुकी है। 'जैम ट्रिनिटी' के कारण 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी तंत्र से बाहर किए गए हैं। इस सरकार के इनबिल्ट मेकेनिज़्म में करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन के खिलाफ की लड़ाई लड़नी है। चाहे जो भी शोर मचा ले, लेकिन यह लड़ाई निरंतर चलती रहेगी।

महोदया, अनुच्छेद 370 हटाकर, अंग्रेजों के कानून समाप्त कर, भारतीय न्याय प्रणाली के रिफॉर्म्स लाकर, लीगल सिस्टम में गुणात्मक सुधार लाकर भारत को दशकों के लिए कानून से सुदृढ़ करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, उसको आने वाला समय याद करेगा। आंतरिक सुरक्षा तंत्र को इतना सुदृढ़ किया गया कि आम नागरिक ने देश में इतना सुरक्षित पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गयी है और सीमित क्षेत्र में प्रभाव मात्र रह गया है।

महोदया, जब हमारी सरकार बनी, तब हमने 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र के साथ शुरुआत की। आज हम इससे भी आगे बढ़ कर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की ओर अग्रसर हैं। जिस प्रकार 'जैम ट्रिनिटी' ने इस देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किए, उसी प्रकार trinity of demography, democracy and diversity के साथ सबके प्रयास के द्वारा हम 2047 के विकसित भारत की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं।

अंत में, मैं बशीर भद्र के शब्दों में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के लिए यही कहना चाहूँगा :-

"जिस दिन से चला हूँ मिरी मंज़िल पे नज़र है,
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।"

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

श्री विवेक ठाकुर: सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी की 2014 से शुरू हुई यात्रा ने कई मील के पत्थर देखे, पर कभी रुके नहीं, क्योंकि उनकी मंज़िल यही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। महोदय, मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Motion that has been moved and seconded is: That an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31st, 2024."

There are 102 Amendments to the Motion which may be moved at this stage. Amendments (Nos. 1 to 4) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

1. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

" but regret that the Address does not mention about the exponential rise in inflation and the prices of essential commodities which have been affecting the poor and the middle-class sections of society detrimentally."

2. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the privatization and disinvestment of profitable PSUs which have a devastating impact on the common man by way of taxes levied on them."
3. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the Government's plan to revamp health and education by increasing funding."
4. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
" but regret that the Address does not mention about falling allocations for MNREGA and the increasing demand for MNREGA work."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 5 to 7) by Shri Vaiko and Shri M. Shanmugam. Are you moving?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I move:
5. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret to say that the Address does not mention about the need to review the provisions of the Constitution dealing with Role of Governors, since it is the colonial legacy."
6. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about extending ESI benefits to workers in the unorganized sector and to extend EPF scheme to them."
7. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret to say that the Address does not mention about eradicating poverty and unemployment and generating more job opportunities."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 8 to 13) by Shri Vaiko; not present. Not moved. Amendment (No. 14) by Shri Elamaram Kareem and Dr. V. Sivadasan. Are you moving?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:
14. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention the need to extend the benefit of MGNREGA to every individual jobseeker."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 15 and 16) by Shri Elamaram Kareem, Shri A. A. Rahim and Dr. V. Sivadasan. Are you moving?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

15. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to Address the burning issue of price rise and particularly the price of petrol and diesel."

16. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the shrinkage and deepening recessionary tendencies in the core sectors of the economy."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 17) by Shri Elamaram Kareem, Shri A. A. Rahim. Are you moving?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

17. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the issues of growing unemployment, loss of lakhs of jobs because of the privatization and disinvestment of public sectors, etc. "

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 18 to 23) by Shri M. Shanmugam. Are you moving it?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I move:

18. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to apportion certain percentage of GST collections to the funding of various Labour Welfare Boards which were getting cess funding through the respective Labour Welfare Acts which were subsumed in the GST Act after the introduction of GST, with the result no funds are provided for their schemes.

19. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to revive and expedite the Sethusamudram Ship canal project which would benefit the economy and increase maritime trade for the country."

20. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to increase the EPF minimum monthly Pension to Rs.7500 along with dearness allowance, as demanded by various trade union organisations."

21. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention the need to hold bipartisan meetings with the trade unions on all important matters relating to labour issues."

22. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about the need to provide all basic facilities like fixed wages, insurance, risk allowance to ASHA and Anganwadi workers immediately."

23. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret to say that the Address does not mention about giving preferential employment to health workers, nurses and para medical staff who were engaged for health emergency during the Covid pandemic, but retrenched later on."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 24) by Dr. V. Sivadasan, not present. Not moved. Amendments (Nos. 25 to 34) by Dr. Ashok Kumar Mittal. Are you moving it?

DR. ASHOK KUMAR MITTAL (Punjab): Sir, I move:

25. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for focus on learning outcomes in education and the need to calculate and qualitatively assess the same."

26. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing unemployment and the jobless growth phenomenon in the country."

27. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the effective steps proposed to be taken to control rising inflation in the country."

28. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about fixing the minimum support price of various agricultural products and also to provide legislative backing to minimum support price mechanism."

29. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to increase budgetary allocation for the health sector so as to achieve the target of allocating 2.5 percent of GDP for health."

30. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention aboutthe need to provide a Special Financial Package for the State of Punjab."

31. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to constitute a National

Commission for Farmers with a constitutional status for the development of our farmers."

32. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any programme for the welfare of shopkeepers in the country."

33. That at the end of the Motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing appropriate reforms in the present education system to make it employment oriented.v

34. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures being taken to control the steep fall in ground water level and to encourage rain water harvesting in the country."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 35 to 41) by Prof. Manoj Kumar Jha, not present. Not moved. Amendments (Nos. 42 to 46) by Shrimati Jebi Mather Hisham. Are you moving it?

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I move:

42. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures taken to prevent train derailments through the adoption of fully mechanized methods of track maintenance, as recommended by the CAG."

43. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the concrete measures to bring price rise under control."

44. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures taken to control 5.69% retail inflation in the country and 10.4% food inflation in urban India."

45. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing Petrol and Diesel within the ambit of GST."

46. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the conduct of Census without further delay."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 47 to 54) by Shri Raghav Chadha, not present. Not moved. Amendments (Nos. 55 to 63) by Shri Sandosh Kumar P. Are you moving it?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

55. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the fact that the New Education Policy will result in increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education to the children belonged to the poor."

56. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the increasing incidents of crime against women and children in the country."

57. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to recognize the "scheme workers" numbering a crore in the country mostly women working under various schemes of the government of India, as workers as per the recommendations of the 45th Indian Labour Conference making them eligible for PF, ESI and other social security benefits."

58. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to expand the workdays to minimum 200 days in a year and to increase the remuneration of the workers under the MGNREG Scheme and implement similar scheme in urban areas also to solve the urban unemployment problem."

59. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the ongoing mass scale contractorization and casualization of regular and perennial work in industries and the need to ensure same wages and benefits for contract/casual/outsourced workers doing the same work as regular workers."

60. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the large-scale privatization of production units of Railways and outsourcing of more than 60 % of the regular activities of routine nature in Railways."

61. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention of the fact that the four labour codes enacted, amalgamating various labour laws will take away almost 90 per cent of the existing workforce out of the purview of the labour legislations and the need to scrap the four labour codes restoring the old labour laws."

62. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the fact that the commitment given to the farmers on MSP and procurement has not been implemented as yet."
63. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—
"but regret that the Address does not mention that despite the claim of the fast-growing economy, what we experience is jobless growth and the inequality in the economy is widening."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 64 to 70) by Dr. John Brittas. Are you moving it?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:
64. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the concern over the freedom of Press in the country as evident from the World Press Freedom Index 2023, published by Reporters without Borders, where India plummeted to its lowest-ever ranking of 161st out of 180 countries, consistently declining since 2016 when it held the 133rd position."
65. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the growing inequality in the country in the distribution of wealth between rich and poor, with the richest 1 per cent own more than 40 per cent of the country's total wealth, while the bottom 50% of the population share just 3% of wealth."
66. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about meeting the demands of the state governments to extend the GST Compensation for another five years as well as to exclude state public account balances and borrowings of state government entities in the computation of the net borrowing ceiling of the States."
67. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:
"but regret that there is no mention in the Address about the growing attacks against minority communities, specifically Muslims and Christians."
68. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:
"but regret that there is no mention in the Address about the need to curb the inflation and the price rise of the essential commodities in the country as well as to bring legal guarantee by way of MSP for all agricultural produces".
69. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:

"but regret that there is no mention in the Address about the adverse impact of demonetisation on economic growth and the deepening recessionary conditions in the Indian economy."

70. That at the end of the Motion, the following be added, namely-:

"but regret that there is no mention in the Address about the need to extend the benefits of MGNREGS to every individual job seeker."

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, आप उनके नाम पर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is enormously talented, और उनके वकील भी तो आप हैं!

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं देश का वकील हूँ, सर।

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Otherwise, many people may come to you. Amendments (Nos. 71 to 77) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Are you moving it?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I move:

71. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the steps to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities."

72. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the loss of jobs and the proactive measures taken to tackle the huge unemployment problem in the country."

73. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the measures to allocate 6% GDP in Health care and development of health infrastructure."

74. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the need to provide adequate financial support to the state like Tamil Nadu affected badly due to heavy rains and floods."

75. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the measures taken by the Government to stop the crimes against women children and elderly persons."

76. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the steps taken by the Government to achieve its goal to double the income of farmers in the country."

77. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the various steps taken by the Government to expedite the Station redevelopment works at Chennai Egmore Railway Station and Chennai Central Railway Station."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 78 to 84) by Shri R. Girirajan. Are you moving it?

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, I move:
78. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the steps taken by the Government to provide adequate financial support to Government of Tamil Nadu which was affected very badly due to heavy rains and inundation."
79. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the various remedial steps taken by the Government to stop the farmers suicides during last few years in various parts of the country."
80. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about need to provide adequate matching funds for the construction of Chennai Metro Rail Project — Phase —II and for the implementation of various Railway projects in Tamil Nadu."
81. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the construction of Sethusamudram Ship CanalProject which is very important for maritime trade and commerce in India and several Port development projects in Tamil Nadu as well as the development of Cruise Services in Tamil Nadu."
82. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the effective measures and welfare schemes by the Government to double the income of farmers in the country."
83. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the steps being taken for the construction of Green Field Airport at Parandur in Tamil Nadu and the expansion of Madurai Airport as well as the establishment of Airports at Vellore, Neyveli."
84. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —
"but regret that the Address does not mention about the universal social security for the unorganized sector workers and creation of a National Social Security Fund with

adequate resources as per the commendations of the National Social Security Board for unorganized Workers."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 85 to 92) by Shri Shaktisinh Gohil. Are you moving it?

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I move:

85. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the huge increase in deaths due to heart attack after the corona vaccination."

86. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the unemployment."

87. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the amount of black money deposited in foreign countries and the amount which has been got backfrom there during the last ten years."

88. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about our fishermen who were picked up by the Pakistani Marines from the shores of Gujarat and many fishermen who are in Pakistan's captivity."

89. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about resuming the special subsidy in the railways' journey for the elderly, journalists and special category people, which has been discontinued by the government since the Corona period."

90. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the vacant posts in government jobs and how to fill them."

91. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the numerous vacant posts of professors in the central universities and how to fill them."

92. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that the address does not mention about the considerable increase in the prices of petrol, diesel and cooking gas and the people of the country are very troubled by inflation."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 93 to 94) by Shri M. Mohamed Abdulla. Are you moving it?

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I move:

93. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide adequate financial support to the state like Tamil Nadu which are affected badly due to heavy rains and floods."

94. That at the end of the Motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the steps being taken for the construction of AIIMS at Madurai in Tamil Nadu."

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 95 to 101) by Shri A.D. Singh. Are you moving it?

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, I move:

95. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about granting Special Category Status to the State of Bihar."

96. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the granting special financial assistance to the tune of Rs. 2.5 Lakhs crores to the State of Bihar as desired by the State Government to undertake developmental work and welfare schemes in the State for removing the backwardness of the State nor it envisages any list of developmental works to be done by Central Government akin to the one prescribed in Schedule 13 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014."

97. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the conducting a nationwide Caste Survey to know the exact percentage of Other Backward Classes in the country."

98. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the about increasing the retirement age and salaries of the scientists engaged in the various departments of the Government."

99. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any concrete plan to protect the Himalayan Glaciers by regulating the indiscreet development activities jeopardizing the lives of people living in Himalayan States."

100. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to regulate the use of AI techniques in various fields."

101. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the stand of the Government towards the Houthis attacks on merchant ships plying through Suez Canal."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 102) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I move:

102. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing disparity in income of the poor and the rich."

SHRI DIGVIJAYA SINGH: But, at the same time, Sir, *

MR. CHAIRMAN: Shri Digvijaya Singh, you can move an Amendment which I authorize. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. The Motion and the Amendments moved thereto are now open for discussion.

The questions were proposed.

RULINGS BY THE CHAIR - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before I go to the list of speakers, hon. Member, Shri Digvijaya Singh, had raised a point of order.

As per practice, after the Motion of Thanks on the President's Address is moved by a Member and seconded by another Member, the Members who have given notice for Amendments thereto are called to move their Amendments. It has been categorically said so. In this regard, the practice is regulated by Rule 242 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) regarding, inter alia, order of speeches. Accordingly, the mover of a motion has the right to speak thereon immediately after moving the Motion. And, similarly, the seconder would also speak after seconding the Motion. Thereafter, the Motion becomes the property of the House and Amendments may be moved thereto by other

* Not recorded.